- 19th Year
- Issue: 293
- 04.03.2026 (WEDNESDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

# कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

# पीएम मोदी का उद्योग जगत को मंत्र, मजबूत इंडियन ईकोनॉमी दुनिया की उम्मीद, अब निर्यात पर हो जोर

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और उद्योग जगत के नेताओं से भारत की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए अधिक निर्माण, उत्पादन और संपर्क स्थापित करने की रणनीति को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्थिक विकास को बनाए रखना और मजबूत करना विषय पर आयोजित बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आर्थिक स्तंभ, विनिर्माण, रसद और एमएसएमई, आपस में जुड़े हुए हैं।मोदी ने कहा कि हमारी दिशा और संकल्प स्पष्ट हैं। अधिक निर्माण करें, अधिक उत्पादन करें, अधिक संपर्क स्थापित करें और अब हमें अधिक निर्यात करने की आवश्यकता है। यह निश्चित है कि आज आप सभी जो सुझाव

देंगे, वे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी जानते हैं कि विनिर्माण, रसद, एमएसएमई... अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का मजबूत विनिर्माण नए अवसर पैदा करता है। उन्होंने कहा कि मजबूत विनिर्माण इन सभी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करता है।

मोदी ने कहा कि हमें इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल उत्पाद बनाने होंगे; तभी हम इन अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। और अब मुक्त व्यापार समझौता लागू हो चुका है, विकास का यह राजमार्ग आपके लिए तैयार है। आज भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ही दुनिया की आशा है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तेज़ आर्थिक प्रगति एक विकसित भारत की प्रमुख नींव है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि, अब हमें अनुसंधान में भारी निवेश करना होगा और वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवज़ा सुनिश्चित करनी होगी। भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार समझौतों के माध्यम से हमारे लिए अवसरों के विशाल द्वार खुल गए हैं, जिससे गुणवज़ा से कभी समझौता न करना हमारी राष्ट्रीय जिज़्मेदारी बन जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे उत्पादों की गुणवज़ा न केवल वैश्विक मानक के अनुरूप होनी चाहिए, बल्कि उससे भी आगे निकल जानी चाहिए। उन्होंने उद्योगों को सलाह दी कि वे उत्पाद बनाने के लिए अन्य देशों की जरूरतों और वहां के लोगों की अपेक्षाओं का अध्ययन और अनुसंधान करें। बजट के विशिष्ट प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने बायोफार्मा शक्ति मिशन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा बजट में भी की गई है। इस मिशन का उद्देश्य भारत को बायोलॉजिज़्स और अगली पीढ़ी की चिकित्साओं का वैश्विक केंद्र बनाना है। हम उन्नत बायोफार्मा अनुसंधान और विनिर्माण में अग्रणी बनना चाहते हैं। आज, दुनिया भरोसेमंद और मजबूत विनिर्माण साझेदारों की तलाश में है।

उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के वर्तमान पुनर्गठन को भारत के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए उद्योग, विज़ीय संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयास का आह्वान किया। मोदी ने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए उद्योग, विज़ीय संस्थानों और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप उत्पादन और विनिर्माण बढ़ाने, लागत संरचना को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, निवेश प्रवाह को तेज करने और भारत के सुदूरतम क्षेत्रों को विकसित करने जैसे विषयों को प्राथमिकता दें। इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपके सुझाव अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।

## मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने किया खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से साधा संपर्क

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को खाड़ी क्षेत्र के दो प्रमुख नेताओं से बात की और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच वहां के नागरिकों की सुरक्षा पर भारत के विशेष ध्यान को रेखांकित किया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, कुवैत के युवराज शेख सबाह अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह और कतर के प्रधानमंत्री शेख तमीम बिन हमद अल थानी से अलग-अलग फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान, उन्होंने अपने-अपने देशों में हुए हालिया हमलों पर चिंता व्यक्त की और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के कल्याण और सुरक्षा की रक्षा के महत्व पर बल दिया। सोमवार को इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य पूर्व के प्रमुख नेताओं से अलग-अलग टेलीफोन पर बातचीत की, ज़्योंकि क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। राजा अज़्दुल्ला द्वितीय से बातचीत में, मोदी ने अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत की चिंता व्यक्त की। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और जॉर्डन में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राजा को धन्यवाद दिया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहज़्मद बिन सलमान अल सऊद और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से बात की और दोनों देशों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया हमलों की निंदा की। मोदी ने इन देशों में चल रही शत्रुता के बीच भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के उपायों पर भी चर्चा की।

भारतीय प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के राजा अज़्दुल्ला द्वितीय से भी बात की और अपनी चिंता व्यक्त की। रविवार को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान में किए गए बड़े पैमाने पर सैन्य हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव तेज़ी से बढ़ गया। ये हमले बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों और नौसैनिक पोतों को निशाना बनाकर किए गए, जो हाल के वर्षों में इस क्षेत्र के सबसे भीषण टकरावों में से एक है।ईरान के कई इलाकों में बड़े विस्फोटों की खबर मिली। तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इमारतें हिल गईं और आसमान में घना धुआं उठ गया।

## लोकसभा की विशेषाधिकार समिति का गठन, भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद को मिली अध्यक्षता की कमान

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को आधिकारिक तौर पर मनोनीत किया, जो 3 मार्च, 2026 से प्रभावी होगा। संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए गठित इस समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता रवि शंकर प्रसाद करेंगे। मनोनीत अन्य सदस्यों में बृजमोहन अग्रवाल (भाजपा), तारिक अनवर (कांग्रेस), मणिकम टैगोर बी (कांग्रेस), टीआर बालू (डीएमके), कल्याण बनर्जी (एआईटीसी), श्रीरंग अप्पा चंदू बर्ने (शिव सेना), रामवीर सिंह बिधूड़ी (भाजपा), संगीता कुमारी सिंह देव (भाजपा), जगदंबिका पाल (भाजपा), त्रिवेंद्र सिंह रावत (भाजपा), अरविंद गणपत सावंत (शिव सेना (यूबीटी), जगदीश शेट्टार (भाजपा), मनीष तिवारी (कांग्रेस) और धर्मेंद्र यादव (समाजवादी पार्टी) शामिल हैं। विशेषाधिकार समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने, अवमानना की

शिकायतों का समाधान करने और संसदीय कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इसका गठन विधायी निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है। यह समिति अध्यक्ष द्वारा संदर्भित मामलों की जांच करने और विशेषाधिकार हनन के आरोपों से संबंधित मामलों पर रिपोर्ट देने के लिए जिज़्मेदार होगी, जिससे संसदीय मर्यादा का पालन सुनिश्चित हो सके।जब सदन द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न समिति को संदर्भित किया जाता है, तो समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में समिति के किसी सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है। जहां नियम 227 के तहत अध्यक्ष द्वारा समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है, जो उस पर अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं या उसे सदन के पटल पर रखने का निर्देश दे सकते हैं। हाल ही में, ओम बिरला ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने के कारणों की जांच करने के लिए गठित तीन सदस्यीय जांच समिति का पुनर्गठन किया। लोकसभा की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति 6 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी। अधिसूचना के अनुसार, पुनर्गठित समिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बॉज़्बे उच्च न्यायालय के मुज़्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य शामिल हैं। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और बी.वी. आचार्य पूर्व समिति के सदस्य थे, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

## खामेनेई की हत्या पर चुप्पी भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल-सोनिया गांधी

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक प्रमुख दैनिक अखबार द इंडियन एज़्सप्रेस% में लिखे अपने लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर तीखा प्रहार किया है। सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर भारत सरकार के मौन को जिमेदारी से पीछे हटना करार दिया है।उन्होंने कहा, ''एक मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल द्वारा एक दिन पहले किए गए लक्षित हमलों में कर दी गई थी। चल रही वार्ताओं के बीच एक मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक गंभीर दरार पैदा करती है।'' उन्होंने कहा कि फिर भी इस स्तज़्ध कर देने वाली घटना से परे नयी दिल्ली की चुप्पी भी हैरान करने वाली है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार ने न तो हत्या और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा की है।

सोनिया गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार खाड़ी देशों और इजराइल के नेताओं के संपर्क में हैं। विपक्ष का आरोप है कि भारत का वर्तमान रुख केवल एक पक्ष की ओर झुका हुआ लग रहा है, जिससे पारंपरिक रूप से संतुलित रही भारत की विदेश नीति कमजोर हो रही है।इस लेख के बाद अब बजट सत्र के दूसरे चरण में सज़ा पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के आसार बढ़ गए हैं।

## उपेन्द्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना तय! आरएलएम कोटे से एनडीए ने फाइनल किया नाम

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने मंगलवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उज़्मीदवार के रूप में नामित करने की घोषणा की। पार्टी की बिहार इकाई द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नामांकन 5 मार्च को दाखिल किया जाएगा। आरएलएम के राज्य प्रवक्ता नितिन भारती ने यह घोषणा करते हुए बताया कि विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पार्टी नेतृत्व ने सर्वसज़्मति से कुशवाहा के नामांकन का निर्णय लिया है।भारती ने विज्ञप्ति में कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से जुड़े एक प्रमुख नेता उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उज़्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस अवसर पर पार्टी और उसके सहयोगी दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं के उपस्थित रहने की उज़्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने उज़्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें छह राज्यों से नौ नामों को मंजूरी दी गई। यह घोषणा पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने नई दिल्ली स्थित अपने मुज़्यालय से की।बिहार से पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार को उज़्मीदवार बनाया है। असम में तेरश गोवाला और जोगेन मोहन उज़्मीदवार हैं। छज़ीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा और हरियाणा से संजय भाटिया उज़्मीदवार हैं। ओडिशा में मनमोहन सामल और सुजीत कुमार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को उज़्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने राज्यसभा चुनावों के लिए चार उज़्मीदवारों - बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी और कोयल मल्लिक - की घोषणा की थी।

## राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने नितिन नबीन सहित कई चेहरों पर लगाया दांव

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बिहार से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे।

नितिन नवीन फिलहाल बांकीपुर विधानसभा से विधायक है। वहीं, बिहार से शिवेश कुमार को भी बीजेपी राज्यसभा भेजेगी।

असम से भाजपा ने तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को उज़्मीदवार बनाया है जबकि छज़ीसगढ़ से पार्टी ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। हरियाणा से संजय भाटिया भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव में उज़्मीदवार होंगे जबकि उड़ीसा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को पार्टी ने उज़्मीदवार बनाया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने यहां से राहुल सिन्हा को राज्यसभा के लिए उज़्मीदवार बनाया है। राहुल पश्चिम बंगाल में लगातार संगठन के लिए काम करते रहे हैं।

### शुभकामनाएं

**होली के पावन अवसर पर कलिंग समाचार की ओर से हमारे सुधी पाठक, विज्ञापनदाता, हॉकर बंधुओं एवं शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं**

**संपादक**

### अवकाश

**होली के पावन अवसर पर आज 04.03.2026 को कलिंग समाचार कार्यालय में अवकाश रहेगा। अतः हमारा अगला अंक 06.03.2026 को प्रकाशित होगा।**

**व्यवस्थापक**

## बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बेटे के ग्रांड इंट्री, होली पर जेडीयू सौंपेगी बड़ी जिम्मेदारी

पटना ०३/०३ (संवाददाता): जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीरज कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में जरूर आना चाहिए। यह तब हुआ जब बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने पुष्टि की कि निशांत कुमार होली के अवसर पर पार्टी में शामिल होंगे और उन्हें बड़ी जिज़्मेदारी सौंपी जाएगी। नीरज कुमार ने यह भी सुझाव दिया कि निशांत कुमार राज्यसभा जाने के योग्य हैं। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की यही अपेक्षा है कि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए... ऐसे लोगों को राजनीति में जरूर आना चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि राज्यसभा कौन जाएगा। लेकिन ज़्या कोई उनकी योग्यता पर सवाल उठा सकता है? ज़्या उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है? अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को जनजीवन में जरूर आना चाहिए।

नीरज कुमार ने आगे कहा कि अगर तेजस्वी यादव और निशांत की तुलना करें, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ चार राज्यों में मामले दर्ज हैं। निशांत कुमार शिक्षा के क्षेत्र में उनसे कहीं आगे हैं। इसलिए दोनों की कोई तुलना नहीं है। अब बिहार के युवा यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि निशांत कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। इससे पहले, श्रवण कुमार ने एएनआई से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि यह कदम पार्टी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता की मांगों के जवाब में उठाया गया है।

श्रवण कुमार ने कहा कि होली के अवसर पर, बिहार के युवाओं और जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार, निशांत कुमार पूरी तरह से पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी तय करेगी कि उन्हें ज़्या जिज़्मेदारी सौंपी जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें बड़ी जिज़्मेदारी दी जाएगी। हम बहुत खुश हैं। बिहार के मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को कहा कि निशांत को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। चौधरी ने उन्हें एक शिक्षित इंजीनियर बताया जो नीतीश कुमार की शैली, शालीनता और सादगी को दर्शाता है।

2025 के विधानसभा चुनावों में बिहार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की भारी जीत के बाद से निशांत कुमार के राजनीतिक प्रवेश को लेकर अटकलें जारी हैं। दिसंबर 2025 में, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार की उपस्थिति में कहा कि पार्टी के सदस्य और समर्थक चाहते हैं कि वह पार्टी के लिए काम करें। उन्होंने आगे कहा कि उनके प्रवेश का समय निशांत का निर्णय है।

# विविध समाचार

## गांधी परिवार पर भाजपा का वसूली वाला प्रहार, व्हाट्सएप चैट दिखा कहा-टिकट के लिए मांगे 7 करोड़

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कांग्रेस नेतृत्व पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि गांधी-वड्रा परिवार के सदस्यों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता से 7 करोड़ रुपये की उगाही करने की कोशिश की। पार्टी ने दावा किया कि कथित व्हाट्सएप चैट से भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया सबूत सामने आए हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पूरा देश सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा कर रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट और मिलीभगत में बेनकाब हो गई है, और इस भ्रष्टाचार का सरगना गांधी-वड्रा परिवार है।

भंडारी ने आरोप लगाया कि हरियाणा की बावल विधानसभा सीट के संबंध में प्रियंका गांधी वड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत सामने आए हैं। भाजपा

नेता के अनुसार, हरियाणा महिला कांग्रेस महासचिव के पति गौरव कुमार ने कुछ व्हाट्सएप चैट और बातचीत सार्वजनिक की हैं, जिनका संबंध कथित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से है। भंडारी का दावा है कि इन चैट से पता चलता है कि वरिष्ठ नेताओं ने बावल विधानसभा का टिकट देने के बदले में 7 करोड़ रुपये की मांग की थी।

उन्होंने केसी वेणुगोपाल का नाम लिया, जिन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी सहयोगी बताया। इसके अलावा उन्होंने कोडिक्कुन्निल सुरेश और प्रियंका गांधी वाड्रा की निजी सहायक (पीए) सदाफ खान का नाम भी कथित बातचीत में लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की कांग्रेस नेताओं में से एक ने खुद ही उन तथ्यों को उजागर किया है और सार्वजनिक किया है जिनमें व्हाट्सएप चैट के जरिए पता चलता है कि प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया - वही केसी वेणुगोपाल जिन्हें राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार का सबसे करीबी माना जाता है। उन्होंने केसी वेणुगोपाल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करके कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 7 करोड़ रुपये की उगाही की - हम जिस शख़्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वह है उकसाना-और वह कोई आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि हरियाणा महिला कांग्रेस की महासचिव थीं। इसके बदले में उन्होंने बावल सीट देने का वादा किया था।

उन्होंने आगे कहा कि वाड्रा की पीए सदाफ खान, वेणुगोपाल के पीए अनस और कोडिक्कुन्निल सुरेश से जुड़ी व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर सार्वजनिक किया गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आज आप सबके सामने सबूत आ गए हैं कि प्रियंका वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के भीतर अपने ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 7 करोड़ रुपये लूटने की कोशिश की। और ये मामूली आरोप नहीं हैं; प्रियंका वाड्रा की पीए, सदफ खान, केसी वेणुगोपाल के पीए अनस और कोडिक्कुन्निल सुरेश से जुड़े व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए। ये सभी सार्वजनिक, लिखित व्हाट्सएप बातचीत हैं।

## बिहार में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, राज्यसभा की सभी सीटों पर जीत का दावा, 5 मार्च को नामांकन

०३/०३ (संवाददाता): बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय साराओगी ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सभी उज़्मीदवार 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। निर्धारित मतदान 16 मार्च को होगा और एनडीए को सभी सीटों पर जीत का पूरा भरोसा है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी उज़्मीदवार 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और एनडीए के उज़्मीदवार सभी सीटें जीतेंगे।

इस बीच, भाजपा ने मंगलवार को आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए अपने उज़्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें छह राज्यों से नौ नामों को मंजूरी दी गई है।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह घोषणा पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपने नई दिल्ली स्थित मुज़्यालय से की। बिहार से पार्टी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और शिवेश कुमार को चुना है। असम में तेरश गोवाला और जोगेन मोहन उज़्मीदवार हैं, जबकि छज़ीसगढ़ में लक्ष्मी वर्मा चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा से संजय भाटिया उज़्मीदवार हैं।

ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे, और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को चुना गया है।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने घोषणा की है कि आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा, उसी दिन शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी और यह प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी हो जाएगी। ये चुनाव 10 राज्यों - महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छज़ीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना - की 37 सीटों पर होंगे, जिनके पदाधिकारियों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की गई थी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च, नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 9 मार्च है।

बिहार भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उपमुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं के साथ होली मनाई। पार्टी अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस दिन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह बिहार और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है। संजय सरावगी ने कहा कि यह बिहार और भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा दिन है। इस वर्ष, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होली मनाई... आइए हम सब मिलकर इस हर्षोल्लास के त्योहार को मनाएं।

## महिला दिवस पर आएगा ऐतिहासिक बजट, विज़ मंत्री हरपाल सिंह ने किए बड़े दावे

नयी दिल्ली०३/०३ (संवाददाता): पंजाब के विज़ मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि 8 मार्च को पेश होने वाला पंजाब सरकार का आगामी राज्य बजट ऐतिहासिक होगा, जिसमें पिछले चार वर्षों में उत्पाद शुल्क और जीएसटी राजस्व में हुई वृद्धि को दर्शाया गया है। एएनआई से बात करते हुए चीमा ने कहा कि महिला दिवस यानी 8 मार्च को पेश होने वाला हमारा बजट ऐतिहासिक होगा। हमने पिछले चार वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

उत्पाद शुल्क हो या जीएसटी, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में उसके खजाने में 27,395 करोड़ रुपये का उत्पाद शुल्क राजस्व आया था। आज तक, 46 महीनों में, हमें 37,975 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, जीएसटी की

बात करें तो, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में केवल 61,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, लेकिन हमारे चार साल के कार्यकाल में हमने 83,000 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया है। राजस्व आंकड़ों का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में उत्पाद शुल्क संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में जीएसटी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

इससे पहले, 26 फरवरी को पंजाब विधानसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी कर पंजाब राज्य की सोलहवीं विधानसभा को 6 मार्च को अपने बारहवें बजट सत्र के लिए बुलाया था। 26 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार, यह सत्र गुलाब चंद कटारिया द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के तहत प्रदज़ शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुलाया गया है। सदन 6 मार्च को सुबह 11:00 बजे पंजाब विधानसभा हॉल, विधानसभा भवन, चंडीगढ़ में एकत्रित होगा।

इससे पहले, चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुज़्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमने पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) के निर्णय के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो सत्र को बढ़ाया जाएगा। हम रविवार, 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी रविवार को संसद चला सकते हैं, तो ज़्या हम नहीं चला सकते? 8 मार्च सिर्फ एक रविवार नहीं है; यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।

भगवंत मान ने 40 लाख परिवारों के लिए मेरी रसोई योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य सरकार राशन किट वितरित करेगी। उन्होंने कहा कि मेरी रसोई योजना से 40 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाला गेहूं पहले की तरह ही वितरित किया जाएगा और इसकी गुणवज़ा में भी सुधार हुआ है। अब पंजाब के भोजन को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए हम यह योजना शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत पंजाब सरकार 40 लाख परिवारों को राशन किट वितरित करेगी। गेहूं के साथ दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर तेल दिया जाएगा।

## युमनाम खेमचंद सिंह बने मणिपुर के नए सीएम, राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

इंफाल ०३/०३ (संवाददाता): युमनाम खेमचंद सिंह ने बुधवार को मणिपुर के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक भवन में राज्यपाल अजय भल्ला ने उन्हें शपथ दिलाई। सिंह को एक दिन पहले ही नई दिल्ली में भाजपा के विधायक दल का नेता चुना गया था। इस बैठक में भाजपा के 37 विधायकों में से 35, पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुघ, पूर्वोज़र प्रभारी

संबित पात्रा और भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मणिपुर के मुज़्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा कि मणिपुर विकसित भारत 2047 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मणिपुर में 36 समुदाय हैं, और हम राज्य में शांतिपूर्ण वातावरण लाने की आशा करते हैं। उनके साथ ही कुकी गांव की भाजपा विधायक नेमचा किपगेन ने मणिपुर की उपमुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से शपथ ग्रहण किया। नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक एल. डिखो ने भी उपमुज़्यमंत्री के रूप में शपथ ली।राजनीति के अलावा, खेमचंद सिंह का ताइक्वांडो से भी लंबा जुड़ाव रहा है। ज़्लैक बेल्ट धारक, वे भारतीय ताइक्वांडो महासंघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और पूर्वोज़र में इस खेल को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। हालांकि वे दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, 62 वर्षीय नेता ने 2017 में इज़्फाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा में पदार्पण किया। वे एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार के दौरान मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए।2022 में, खेमचंद सिंह ने बीरेन सिंह की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने नगर प्रशासन, आवास और शहरी विकास (एमएएचयूडी), ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला।

## मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर सरकार की पैनी नजर, 25 दिन का तेल का भंडार तैयार, अभी दाम नहीं बढ़ेंगे

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि भारत के पास 25 दिनों के कच्चे तेल और परिष्कृत तेल का भंडार है। सूत्रों ने यह भी कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल वृद्धि की कोई योजना नहीं है। ब्रेंट ज़रूड की कीमत लगभग 80 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है - ईरान संकट के बाद से लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि - और इसके और बढ़ने की आशंका है ज़्योंकि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक, होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है।

भारत के लिए, ऊंची कीमतों का मतलब आयात बिल में वृद्धि है। भारत अपनी जरूरत के लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है - जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के लिए कच्चा माल है - जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक मध्य पूर्वी देशों द्वारा आपूर्ति किया जाता है और संकरे होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है, जिससे ईरान

संकट के बीच आपूर्ति बाधित हो गई है। अमेरिका और इज़राइल ने सप्ताहांत में ईरान में सैन्य हमले किए। तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इज़राइल और अमेरिकी सेनाओं की मेज़बानी करने वाले देशों, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल हैं, पर मिसाइलें और ड्रोन दागे।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरू मध्य लगभग बंद हो गया है, जो वैश्विक ऊर्जा प्रवाह का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। विश्व के समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल के निर्यात का लगभग एक तिहाई और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस की खेपों का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा इसी संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है। भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जो अपनी कच्चे तेल की लगभग आधी आवश्यकता संकरी जलडमरूमध्य से पूरी करता है। कतर, जो भारत का प्रमुख द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आपूर्तिकर्ता है, वह भी इसी जलडमरूमध्य का उपयोग करके भारत को ईंधन भेजता है।जलडमरू मध्य बंद होने की स्थिति में, भारत मध्य पूर्व से तेल की कमी को पूरा करने के लिए पश्चिम अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं से तेल ले सकता है। भारत कमी को पूरा करने के लिए रूस से भी तेल ले सकता है। भारत ने 2024-25 में 23.7 मिलियन टन (474,000 बैरल प्रति दिन) पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया, जो देश की ईंधन खपत का 10 प्रतिशत है।

## मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी की बड़ी मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सद्भाव बढ़ेगा

नयी दिल्ली ०३/०३ (संवाददाता): अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने से सामाजिक सद्भाव मजबूत होगा। इस्लामी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि गाय के दूध में औषधीय गुण होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जबकि गोमांस का सेवन बीमारी का कारण बन सकता है।

उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने %गोदान% नामक फिल्म का पोस्टर जारी किया है।

यह पोस्टर और यह फिल्म गायों से संबंधित है। इसमें संभवत: गायों के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव से जुड़ी कहानियां हैं। मैं उज़र प्रदेश सरकार और भारत सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करता हूं। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से कई समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, तो आपको गायों से जुड़े कई विवाद मिलेंगे। इसलिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी।

उन्होंने मुसलमानों को गाय का मांस न खाने और गाय पालन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी ताकि उनके दूध से लाभ उठाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस्लामी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पैगंबर मुहज़्मद (उन पर शांति हो) की एक हदीस के अनुसार, गाय के मांस में रोग होता है और उसके दूध में शिफा (इलाज) होता है। पैगंबर का उद्देश्य और दृष्टिकोण यह था कि गाय की रक्षा, सेवा और संरक्षण किया जाए, उसका मांस न खाया जाए, बल्कि उसके दूध से लाभ उठाया जाए। स्वयं दूध का सेवन करें और अपने परिवार, बच्चों और बीमारों को भी दें ताकि वे स्वस्थ हो सकें। मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूँ गाय पालें और गाय का मांस न खाएँ। स्वयं गाय का दूध पिएं, अपने बच्चों को पिलाएं और बीमारों को भी दें ताकि वे स्वस्थ हो सकें।

**कलिंग समाचार**
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

# विविध समाचार

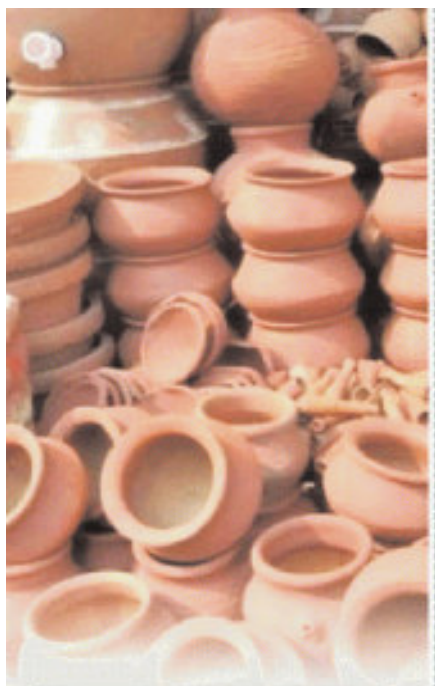

## सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं मिट्टी के बर्तन

**प्राचीन काल से ही मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता आ रहा है। हालांकि वर्तमान समय में मिट्टी के बर्तनों की जगह प्लास्टिक या अन्य धातु से बने बर्तनों ने ले ली है। लेकिन आज भी सजावट के लिए ज्यादातर लोग मिट्टी से बनी चीजों का प्रयोग करते हैं।**

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मिट्टी के बर्तन व्यक्ति की बंद किस्मत को जगा सकते हैं। विद्वानों के अनुसार, घर पर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जानिए वास्तु में किन तीन मिट्टी की चीजों को घर पर रखना शुभ माना जाता है।

### मिट्टी का घड़ा

वास्तु के अनुसार, मिट्टी का घड़ा रखने से सुख-समृद्धि घर आती है। मिट्टी का घड़ा सदैव उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। इसके साथ ही घड़े को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि घर पर मिट्टी का घड़ा रखने से सुख-समृद्धि का वास होता है। आपको बता दें कि आज भी आयुर्वेदाचार्य मिट्टी के घड़े का पानी सेहतमंद बताते हैं।

### मिट्टी का प्रतिमाएं

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, पूजा स्थल पर मिट्टी से बनी देवी-देवताओं की प्रतिमाएं रखना शुभ हता है। इसलिए घर के मंदिर में हमेशा मिट्टी से बनी देवी-देवताओं की मूर्ति रखनी चाहिए। इन प्रतिमाओं को हमेशा घर के ईशान कोण (उत्तर-पूर्व दिशा) या दक्षिण-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

### मिट्टी का दीपक

वर्तमान समय में पूजा स्थल पर मिट्टी के दीपक का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के दीपक की जगह धातु से बने दीपक का इस्तेमाल होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, मिट्टी से बने दीपक को घर पर जलाना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

## क्या घर के पास मंदिर का होना शुभ है? क्या कहता है वास्तु

भारतीय संस्कृति में मंदिरों का विशेष महत्व है। मंदिर आपके मन को शांति प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। लोग अक्सर अपने घरों और आस-पास के स्थानों में मंदिर बनवाते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पास मंदिर का होना शुभ माना जाता है या अशुभ, यह कई बातों पर निर्भर करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पास मंदिर का निर्माण और उसका स्थान बहुत ज्यादा मायने रखता है। मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि यह मंदिर उचित दिशा और नियमों के अनुसार स्थित है, तो यह घर में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति लाने में मदद करता है। वहीं, यदि मंदिर घर के बहुत नजदीक या गलत दिशा में स्थित है तो यह घर के लिए वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपके पारिवारिक जीवन में बाधाएं और मानसिक तनाव बढ़ सकता है।

### घर के पास मंदिर होने के फायदे

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पास मंदिर होने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिससे परिवार में शांति और समृद्धि आती है। मंदिर से होने वाले नियमित मंत्रोच्चार, आरती और भजन आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। इससे घर के सदस्यों में मानसिक शांति बनी रहती है और तनाव कम होता है। घर के पास मंदिर होने से आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है और पूजा-पाठ में रुचि बढ़ती है। यही नहीं, धार्मिक आयोजनों में भाग लेने का अवसर भी मिलता है, जिससे सामाजिक और धार्मिक जुड़ाव मजबूत होता है। आइए जाने इसके अन्य लाभों के बारे में-

### सकारात्मक ऊर्जा का संचार

मंदिरों में नियमित रूप से पूजा-पाठ, मंत्रोच्चार और आरती होती है, जिससे वहां के आस-पास का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। यदि आपके घर के पास मंदिर है, तो वहां की पवित्रता और आध्यात्मिक शक्ति घर के सदस्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। मंदिर की ऊर्जा घर में रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करती है और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है।

### मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति

यदि आपका घर मंदिर के पास है तो ऐसे स्थान पर रहने से व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है और ध्यान व प्रार्थना के लिए एक पवित्र वातावरण प्राप्त प्राप्त होता है। इससे आपके जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है।

### नकारात्मक शक्तियों से रक्षा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, मंदिरों में नियमित रूप से घंटों की ध्वनि गूंजती है और हवन व यज्ञ होते हैं, जो नकारात्मक शक्तियों और बुरी ऊर्जा को दूर करने में सहायक होते हैं। इस कारण घर के आस-पास मंदिर होना शुभ माना जाता है। जब आपका घर मंदिर के निकट होता है तो इन भजन-कीर्तन और हवन का सुखद प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है और तन और मन शुद्ध बना रहता है।

### सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव

मंदिर सिर्फ पूजा-अर्चना का स्थान नहीं होता है बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का भी केंद्र होता है। मंदिर के पास घर होने से व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है और अपने समुदाय से गहरा जुड़ाव महसूस करता है। धार्मिक उत्सवों, सत्संग और अन्य आयोजनों में भाग लेकर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि मिलती है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक सहयोग और मेल-जोल को भी बढ़ावा देता है। मंदिर का सकारात्मक वातावरण पारिवारिक जीवन में सौहार्द बनाए रखने में सहायक होता है, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मंदिरों के आसपास का क्षेत्र पवित्र होता है और वहां रहने से व्यक्ति का मन धार्मिकता की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि, मंदिर के समीप रहने से व्यक्ति को पुण्य लाभ प्राप्त होता है, लेकिन मंदिर से अत्यधिक निकटता कुछ परिस्थितियों में अशुभ भी हो सकती है। कुछ ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ ग्रह प्रभावी हो और वह मंदिर के पास रहता हो, तो उसे विशेष पूजा-पाठ करने की सलाह दी जाती है। घर के पास मंदिर की मौजूदगी आपके लिए कई तरह से सकारात्मक हो सकती है, लेकिन यदि आपके घर में इसके कोई भी नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं तो आपके लिए वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी है।

### क्या घर के पास मंदिर का होना वास्तु अनुसार ठीक है?

- जहां एक तरफ घर के पास मंदिर होने से कुछ लाभ हैं, वहीं कुछ वास्तु कारणों से मंदिर और घर आस-पास होने के नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। आइए जाने इसके बारे में-
- यदि घर के पास बड़ा मंदिर मौजूद हो और वहां हर समय धार्मिक गतिविधियां होती रहती हैं, तो यह कई बार घर के लोगों को उनके दैनिक जीवन और कार्यों में बाधा भी पहुंचा सकता है।
- वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि मंदिर का मुख्य द्वार या गर्भगृह किसी घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने है, तो यह आपके घर के लिए वास्तु दोष उत्पन्न कर सकता है। इससे घर में मानसिक तनाव, आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं।
- कई बार घर के आस-पास मौजूद बड़े मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है, जिससे घर में हमेशा शोर का वातावरण हो सकता है, इससे घर में रहने वालों की दिनचर्या प्रभावित होती है और घर के छात्रों और बुजुर्ग लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव होने लगता है।

### घर के पास में मंदिर है तो आजमाएं वास्तु के ये उपाय

- यदि आपके घर के आस-पास मंदिर मौजूद है और किसी तरह का वास्तु दोष उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ आसान उपाय आजमाकर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है-
- यदि मंदिर का मुख्य द्वार आपके घर के द्वार के ठीक सामने है तो किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से बचने के लिए घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं
- यदि आप मंदिर के ठीक पास रहते हैं तो घर में नियमित रूप से पूजा-पाठ, हवन और मंत्रोच्चार करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
- अगर मंदिर का ऊर्जात्मक प्रभाव घर पर पड़ रहा है, तो घर की खिड़की या दरवाजे के पास हल्के रंग का पर्दा लगाएं या ऊंची दीवार बनवाएं जिससे ऊर्जा का संतुलन बना रहे।
- यदि आपके घर पर मंदिर के कारण बहुत अधिक भीड़ और शोरगुल होता है, तो घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए ध्यान और योग करें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी।

**मंदिर आपके मन को शांति प्रदान करने का एक अच्छा माध्यम माना जाता है। लोग अक्सर अपने घरों और आस-पास के स्थानों में मंदिर बनवाते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो। लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पास मंदिर का होना शुभ माना जाता है या अशुभ, यह कई बातों पर निर्भर करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के पास मंदिर का निर्माण और उसका स्थान बहुत ज्यादा मायने रखता है। मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव घर के वातावरण पर पड़ता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। यदि यह मंदिर उचित दिशा और नियमों के अनुसार स्थित है, तो यह घर में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति लाने में मदद करता है।**

## घर के मंदिर में वास्तु अनुसार रखें मूर्तियों की संख्या

**हिंदू धर्म में सभी भगवानों की विशेष रूप से पूजा करने का विधान है। पूजा के लिए लोग घर के मंदिरों में भगवान की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से घर की सभी चीजों के लिए वास्तु का पालन करना जरूरी है वैसे ही भगवान की मूर्तियों को भी वास्तु के अनुसार ही स्थापित करना चाहिए। घर के मंदिर में आपको हमेशा मूर्तियों की स्थापना करते समय कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन से सभी बाधाओं को दूर करना चाहती हैं और धन को आकर्षित करना चाहती हैं, तो आपको मंदिर में सही संख्या में ही भगवान की मूर्तियां रखनी चाहिए।**

यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रही हैं तो इनकी संख्या दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां न रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकती हैं। एक ही मंदिर के अंदर दो से ज्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप दो मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर रख सकती हैं।

### भगवान कृष्ण की मूर्तियों की संख्या

यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करती है तो ध्यान में रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के दो स्वरुप रख सकती हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की एक ही मूर्ति रखें तो यह आपके लिए शुभ होगा।

### भगवान हनुमान की मूर्तियों की संख्या

यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही है तो एक से ज्यादा मूर्ति न रखें। यदि आप उनकी तस्वीर रख रही हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी के रौद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें, ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती है।

### भगवान शिव की कितनी मूर्तियां हैं शुभ

यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखती हैं तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हों, जिसमें गणपति भी मौजूद हों। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए।

### घर के मंदिर में न रखें ऐसी मूर्तियां

- वास्तु की मानें तो आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण,सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश और दो पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए।
- भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर न रखें, इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है।
- आप देवी-देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति- सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक-एक मूर्ति रख सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां न रखें।
- एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी दो शिवलिंग न रखें।
- किसी भी तरह की खंडित मूर्ति घर के मंदिर में न रखें।

# कलिंग समाचार

# संपादकीय

**बुधवार 04 मार्च 2026**

## विरोध करना अपराध नहीं है

नयी दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इ पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के शर्ट उतार कर प्रदर्शन करने से भाजपा ने देश में ऐसा सियासी बवाल खड़ा किया मानो लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन करना कोई बड़ा गुनाह है। अब इस बात को देखकर हैरानी भी नहीं होती कि भाजपा के साथ-साथ कई स्वयंभू बड़े पत्रकारों ने भी इस प्रदर्शन पर कांग्रेस को नसीहतें देना शुरु कर दिया कि विरोध का ये कोई तरीका नहीं होता। इन पत्रकारों ने शायद अब आईने में अपना चेहरा देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि देखेंगे तो असलियत दिखाई पड़ेगी कि मोदी सरकार के 12 बरसों में एक से बढ़कर एक गलत फैसले पूरी तरह सोच-समझ कर लिए गए, जिनसे आम जनता की जान पर बन आई, लेकिन तब इनके मुंह से ये नहीं निकला कि सत्ता चलाने का ये कोई तरीका नहीं है। नोटबंदी, लॉकडाउन, सांसदों का निलंबन ऐसे बड़े मामले तो छोड़ ही दीजिए, जनता के टैक्स पर प्रधानमंत्री के मन की बात को तमाम भाजपाई मु यमंत्री, मंत्री, विधायक बड़ी स्क्रीन लगाकर सुनते हैं, या प्रधानमंत्री ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए जितना तामझाम करते हैं, उस पर क्या पत्रकारों ने लगातार सवाल उठाए। अगर पत्रकार ईमानदारी से रोजाना सरकार को गलत बात पर टोकते रहे, उससे जुड़े कार्यक्रम करते रहें, तो मजाल है कि कोई सरकार इतनी मनमानी करे, जितनी मोदी सरकार करती है। लेकिन 2014 के बाद एक अलग ही चलन बन गया है कि सारी जि मेदारी विपक्ष पर डाल दी जाती है, सवाल भी विपक्ष से ही होते हैं। पिछले कार्यकाल में अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष थे, तो उनसे उतने सवाल नहीं होते थे, वो कब संसद में आए या संसद सत्र के दौरान कहां रहे, इसकी भी जानकारी पत्रकारों को शायद ही होती होगी। लेकिन राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, सवालों के तीर उनकी तरफ ही रहते हैं। सत्र में व्यवधान हो तो उसके जि मेदार राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री संसद न आएं तो उसके भी जि मेदार राहुल गांधी हैं और अगर सत्र के बीच में दो-चार दिन के लिए राहुल गांधी कहीं चले जाएं, तो उन्हें पार्ट टाइम राजनेता कहने में गुरेज नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कभी कोई सवाल नहीं होता और अब तो पत्रकारों ने ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि आप हर महीने आकर अपने मन की बात सुनाते हैं, तो कभी खुली प्रेस कांफ्रेंस क्यों नहीं करते, ताकि हम भी जनता से जुड़े सवाल सीधे आपके सामने रख सकें। बहरहाल, आज का दौर ऐसा हो चुका है कि अब सरकार के साथ-साथ पत्रकारों से निष्पक्ष रहने की उ मीद भी खत्म होती जा रही है। जहां तक सवाल युवा कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन का है, तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध अधिकार ही होता है, अपराध नहीं होता। 2010 में जब दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे, तब भाजपा ने भी विरोध किया था। तब भी अंतरराष्ट्रीय आयोजन ही था, तो क्या उसमें देश की बदनामी नहीं हुई होगी। असल में भाजपा को देश की नहीं अपनी बदनामी का डर सता रहा है। क्योंकि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम इज़ कॉ प्रोमाइज़्ड लिखी जो टी शर्ट्स दिखाकर विरोध किया, उसमें संदेश दूर-दूर तक पहुंच गया कि हमारे प्रधानमंत्री खुद को या अपने मित्रों के बचाने के लिए किसी भी हद तक झुक कर समझौता कर सकते हैं। वैसे राहुल गांधी यह बात पहले ही संसद में कह चुके हैं और इस आरोप को लगाने की वजह खुद मोदी सरकार ने ही दी है। कांग्रेस उनसे बार-बार पूछ रही है कि आखिर व्यापार सौदे में डोनाल्ड ट्रंप की सारी शर्तों को मानने की कौन सी मजबूरी है। ट्रंप ने केवल भारत पर ही नहीं दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपे हैं, लेकिन चीन जैसे शक्तिशाली देश से लेकर ब्राजील जैसे विकासशील देश ने अपनी शर्तें खुलकर ट्रंप के सामने रखीं और बेजा बातों को मानने से इंकार कर दिया। नरेन्द्र मोदी ऐसा क्यों नहीं कर पाए, किसलिए रूस जैसे पुराने मित्र से तेल खरीदना बंद किया, पांच सौ बिलियन डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदने की शर्त क्यों मान ली। अगर सरकार इनका तार्किक जवाब दे देती तो शायद कांग्रेस को विरोध का मौका नहीं मिलता।

# मतदाताओं को सीधे कैश ट्रांसफर मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

**डॉ. ज्ञान पाठक**

कोर्ट ने चुनावी हार, सीटों के नुकसान, या प्रचार पाने का ज़िक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणी को कानूनी क्षेत्राधिकार के साथ मिलाकर गलती की है। अदालतों से उ मीद की जाती है कि वे राजनीतिक लोकप्रियता को संवैधानिक न्याय से अलग रखें। %व्यवस्थित प्रभाव डालने% की जांच किए बिना याचिका पर सुनवाई से इंकार करना भी गलत है सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव के दौरान चुनावी आदर्श आचार संहिता (एससीसी) लागू होने के बाद मतदाताओं को सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा सीधे कैश ट्रांसफर, भारतीय चुनाव आयोग का इस तरह से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेना, और मतदान के दिन लाभार्थियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार करना अनुचित है क्योंकि इसमें पहचानने योग्य कानूनी कमजोरियां हैं और साथ ही राजनीतिक रंग भी, जिसने एक याचिकाकर्ता राजनीतिक पार्टी को चुनाव में उसकी विफलता के लिए उपहासपूर्ण टिप्पणी की, जबकि आरोप के गुण-दोष में जाए बिना इसे न सुनने के लिए एक आधार बनाया भी बनाया।

शुक्रवार को जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी (जेएसपी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए, भारत के मु य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने और सत्तारूढ़ प्रतिष्ठानों द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपनाई गई भ्रष्ट प्रथा को रोककर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशानिर्देश बनाने और समुचित निर्देश देने की मांग की थी।

सबसे परेशान करने वाली बात मु य न्यायाधीश की राजनीतिक टिप्पणी थी, %आपकी राजनीतिक पार्टी को कितने वोट मिले? लोग आपको खारिज करते हैं और आप लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं। ... हम पूरे राज्य के लिए एक साथ निर्देश जारी नहीं कर सकते, वह भी किसी राजनीतिक पार्टी की पहल पर।% जेएसपी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि बिहार सरकार ने मु यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 10,000 रुपये हस्तांतरित करके चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्ज में डूबे राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का उल्लंघन करते हुए मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 15,600 करोड़ रुपये बांटे।

हम जानते हैं कि जेएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई और उसके ज़्यादातर उ मीदवारों की ज़मानत ज़ब्त हो गई, लेकिन यह भी सच है कि जेएसपी को 16 लाख से ज़्यादा वोट मिले, जो कुल डाले गए वैध मतों का 3.34 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि जेएसपी राज्य के इतने सारे लोगों की आवाज़ है, और इसलिए इसे यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता की चुनावी विफलता और पब्लिसिटी की कथित तलाश के बारे में कोर्ट की बात में और भी कमियां हैं, जैसे कि संवैधानिक न्यायशास्त्र चुनावी सफलता को कानूनी हैसियत के लिए एक मानदंड के रूप में नहीं मानता, या विफलता को न्याय मांगने के अधिकार की ज़ब्ती के रूप में भी नहीं मानता। ऐतिहासिक रूप से, कई बड़े संवैधानिक मामले उन लोगों द्वारा लाए गए थे जो राजनीतिक रूप से हाशिये पर थे।

इसलिए, किसी कानूनी याचिका की स्वीकार्यता तय करते समय याचिकाकर्ता की चुनावी लोकप्रियता को तौलना, संवैधानिक न्यायनिर्णय में एक व्यक्तिपरक और गैर-कानूनी मानक लाने का जोखिम है। न्यायपालिका से उ मीद की जाती है कि वह दावों पर फैसला करे, न कि इरादों पर। कोर्ट मामले का गुणदोष सुने बिना इरादे के बारे में कैसे फैसला कर सकता है? राजनीतिक रूप से असफल पार्टियों को भी चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे मुद्दे उठाने का अधिकार है, क्योंकि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को नष्ट करते हैं और जिससे सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव मैदान में समान अवसर नहीं मिलता और वे इस गड़बड़ी के शिकार होते हैं। ज़्यादा जानें समाचार विश्लेषण युवा उद्यमिता पाठ्यक्रम क्षेत्रीय व्यंजन रेसिपी कोर्ट की दूसरी टिप्पणियों के बारे में आलोचकों ने एक और टिप्पणी पर सवाल उठाया है जैसे कि %किसी को तो उस योजना को ही चुनौती देनी चाहिए थी। वह हमारी प्रार्थना नहीं है। आप बस चुनाव को रद्द घोषित करवाना चाहते हैं,% मु य न्यायाधीश ने कह यह भी जोड़ते हुए, %हम मु त की चीज़ों के मुद्दे पर विचार करेंगे। लेकिन हमें नेक इरादे भी देखने होंगे... हम किसी ऐसी पार्टी के कहने पर ऐसा नहीं कर सकते जो अभी-अभी चुनाव हारी है। जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे।' आखिरी टिप्पणी को पहले लेते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी से यह कहना कि जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी ठीक वैसा ही करेंगे, यह सिर्फ कोर्ट की कल्पना है, और यह एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी की तरह है, न कि कोई ठोस कानूनी विचार। कोर्ट को ऐसी अटकलबाज़ी वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह किसी के कुछ गलत करने से पहले ही उसे नीचा दिखाना है। एक राजनीतिक पार्टी लोकतंत्र में एक स्टेक होल्डर होती है, और शायद मु य न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं हो सकता कि %हम उस पार्टी के कहने पर (फ्री बीज़ के मुद्दे को) नहीं देख सकते जो अभी-अभी चुनाव हारी है।' कोर्ट ने कहा कि फिर हमें नेक इरादे भी देखने होंगे। यह समझना मुश्किल है कि चुनाव हारने वाली राजनीतिक पार्टी द्वारा आदर्श आचार संहिता के साफ तौर पर उल्लंघन वाले मुद्दे को उठाना नेक इरादा क्यों नहीं है। देश का कोई भी नागरिक नेक इरादे वाला होता है, जब तक यह सिद्ध न हो कि उसके इरादे गलत हैं, और इसलिए उसकी बात सुनी जानी चाहिए, वैसी स्थिति में भी जब वह अपने प्रयासों में पूरी तरह विफल रहे। ज़्यादा जानें राजनीति समाचार समाचार चैनल सदस्यता मोबाइल फोन यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सही उपाय हाई कोर्ट में याचिका दायर करना था क्योंकि यह राज्य-विशिष्ट था। हालांकि, सिर्फ राज्य-विशिष्ट होने से अनुच्छेद 32 अपने आप अनुपलब्ध नहीं हो जाता, खासकर जहां अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और अनुच्छेद 14 के तहत समानता जैसे संवैधानिक अधिकारों का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया हो। कोर्ट ने इस बात की जांच ही नहीं की कि चुनावी आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को भ्रष्ट आचरण माना जा सकता है या नहीं। ठीक इसी कारण से, याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीतिक विचारों पर आधारित माना जा रहा है, यानी पार्टी की चुनावी सफलता की कमी, और आरोपों की कानूनी खूबियों के आकलन के बजाय क्षेत्राधिकार जैसी प्रक्रियात्मक तकनीकी बातों के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय का यह विचार कि यह एक चुनावी विवाद जैसा लग रहा था और इसलिए इसे हाई कोर्ट द्वारा तय किया जाना चाहिए, केवल आंशिक रूप से सही है, और सिद्धांत रूप में गलत नहीं हो सकता है। हालांकि, जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के व्यवस्थित उल्लंघन, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, मतदाताओं को बड़े पैमाने पर प्रलोभन या रिश्वत, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का उल्लंघन, और अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत चुनावी पसंद में विकृति जैसे आरोप शामिल होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय का इंकार सही नहीं है। यह खासकर तब है जब सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह तय कर चुका है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। कोर्ट ने चुनावी हार, सीटों के नुकसान, या प्रचार पाने का ज़िक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणी को कानूनी क्षेत्राधिकार के साथ मिलाकर गलती की है। अदालतों से उ मीद की जाती है कि वे राजनीतिक लोकप्रियता को संवैधानिक न्याय से अलग रखें। %व्यवस्थित प्रभाव डालने% की जांच किए बिना याचिका पर सुनवाई से इंकार करना भी गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता ने चुनावी पसंद में व्यवस्थित विकृति का मुद्दा उठाया था जो एक संवैधानिक मुद्दा है, और यह व्यक्तिगत भ्रष्ट आचरण नहीं है जिसे चुनाव याचिकाओं द्वारा निपटाया जाना चाहिए। कोर्ट का इंकार अपने ही संवैधानिक मिसालों और फैसलों के अनुरूप नहीं है। कमजोर या अलोकप्रिय याचिकाकर्ता भी संवैधानिक कमियों को उजागर कर सकते हैं। उन कमियों की शुरुआत में ही जांच करने से इंकार करके, कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका से पीछे हटने के बजाय उसे मजबूत करने का अवसर खो दिया है।

***देश का कोई भी नागरिक नेक इरादे वाला होता है, जब तक यह सिद्ध न हो कि उसके इरादे गलत हैं, और इसलिए उसकी बात सुनी जानी चाहिए, वैसी स्थिति में भी जब वह अपने प्रयासों में पूरी तरह विफल रहे। ज़्यादा जानें राजनीति समाचार समाचार चैनल सदस्यता मोबाइल फोन यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सही उपाय हाई कोर्ट में याचिका दायर करना था क्योंकि यह राज्य-विशिष्ट था। खासकर जहां अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और अनुच्छेद 14 के तहत समानता जैसे संवैधानिक अधिकारों का कथित तौर पर उल्लंघन किया गया हो।***

# भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत के किसानों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगा

**नित्य चक्रवर्ती**

मैं यहां एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित किस्सा बताना चाहता हूं जो यह समझाने में मदद करेगा कि अमेरिकी कृषिलॉबी अपनी सरकार और वैश्विक कृषि व्यापार पर कितना ज़्यादा असर डालती है।

दिसंबर 1999 मेंमैं भारत सरकार के मीडिया प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर अमेरिका के सिएटल में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय स मेलन में शामिल हुआ था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और उन्होंने स मेलन में यूरोपीय यूनियन के देशों से सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की मांग की थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार में उनके मंत्री और वफादार विशेषज्ञों को जनता को यह समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से भारत को क्या-क्या बड़े फायदे हो रहे हैं, खासकर कृषिक्षेत्र को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास लक्षित क्षेत्रों में से एक है। ज़्यादा जानें समाचार बुलेटिन मनोरंजन समाचार युवा उद्यमिता पाठ्यक्रम वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एक बड़े विदूषक की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि वे रोज़ाना मीडिया को दिए जाने वाले अपने प्रायोजित साक्षात्कारों में कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने अड़ियल डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा से ज़्यादा फायदे निकालने में बहुत अच्छा काम किया है। वे यह सब तब कह रहे हैं जब पूरे समझौते की बारीकियां इस साल मार्च के बीच तक ही पता चलेंगी और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर वे किसी भी समय इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो अमेरिका को कभी भी बदलाव करने का हक है। यह ट्रंप के पहले के बयान %मैं कानून हूं, मैं तय करता हूं कि क्या सही है और क्या गलत% जैसा ही है।

मैं यहां एक व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित किस्सा बताना चाहता हूं जो यह समझाने में मदद करेगा कि अमेरिकी कृषिलॉबी अपनी सरकार और वैश्विक कृषि व्यापार पर कितना ज़्यादा असर डालती है। दिसंबर 1999 मेंमैं भारत सरकार के मीडिया प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर अमेरिका के सिएटल में 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय स मेलन में शामिल हुआ था।

उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे और उन्होंने स मेलन में यूरोपीय यूनियन के देशों से सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की मांग की थी। इसके उलट, यूरोपीय यूनियन ने मांग की थी कि अमेरिका अपनी कृषि सब्सिडी कम करे क्योंकि यह रकम अमेरिका के बजट का 50 प्रतिशत थी और 1999 में कुल अमेरिकी कृषि सब्सिडी वैश्विक कृषि सब्सिडी की कुल रकम का 85 प्रतिशत थी।

दोनों विरोधी पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए और आखिर में डब्ल्यूटीओ स मेलन बिना किसी संयुक्त घोषणापत्र जारी हुए ही खत्म हो गई। मैंने अपने अमेरिकी पत्रकार दोस्त से पूछा कि अमेरिका अपनी सारी सब्सिडी बनाए रखने पर इतना अड़ा क्यों है? मेरे दोस्त ने जवाब दिया — अगला राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2000 में होने है। क्लिंटन ने कृषिलॉबी से वायदा किया है कि वह यूरोपीय यूनियन को अपनी सब्सिडी कम करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन क्योंकि वह फेल हो गए, इसलिए 2000 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी पर इसका बुरा असर पड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ। रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका के बड़े किसान समुदाय के बीच प्रचार अभियान चलाया कि क्लिंटन ने यूरोपीय यूनियन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और किसान हार रहे हैं। डेमोक्रेट्स नवंबर 2000 का चुनाव हार गए, जूनियर जॉर्ज बुश रिपब्लिकन पार्टी से नए राष्ट्रपति चुने गए।

ठीक 26 साल बाद, आज अमेरिका में स्थिति बहुत अलग नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप इस साल नवंबर में अपने मध्यावधि चुनाव का सामना कर रहे हैं। उनके लिए संकेत उतने अच्छे नहीं हैं। उन्हें अपनी नीति जारी रखने के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। मध्यावधि चुनाव में हार का मतलब है उनकी शक्ति पर बड़ी रोक, हालांकि वह दो और साल राष्ट्रपति बने रहेंगे। अमेरिका के किसान अमेरिका में किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा मतदाता आधार हैं। 2024 में, अमेरिका के किसानों को सरकारी भुगतान से 9.3 अरब डालर की सब्सिडी मिली, लेकिन ट्रंप के पहले साल में, यह 2025 में चार गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 42.4 अरब डालर हो गई। कितनी बड़ी छलांग है यह? ज़्यादा जानें प्रादेशिक समाचार समाचार सदस्यता आर्थिक समाचार पत्रिका अब इन भारी सब्सिडी के साथ, अमेरिकी किसान भारत में कृषि उत्पादनों के बढ़ते बाजार में उतरेंगे और भारतीय प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए घरेलू बाजार को सस्ते सामान से भर देंगे। पीयूष गोयल अमेरिकी उत्पादकों को बड़े बाजार में प्रवेश दिलाने के बाद भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। यह पूरी तरह बकवास है। यह एक अमीर अमेरिकी शार्क और एक बेचारे भारतीय उत्पादक को एक ही मैदान में उतारकर बराबरी का मौका देने जैसा है। जैसा कि कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में हुआ, अमेरिकी उत्पादक पहले चरण में सस्ता सामान देकर उपभोक्ताओं के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। फिर जब स्थानीय लोग बाहर हो जाएंगे, तो अमेरिकी उत्पादक कीमतें बढ़ा देंगे क्योंकि तबतक दूसरा विकल्प खत्म हो गया होगा। भारत में, हालात शायद इतने बुरे न हों, लेकिन गरीब और मध्यवर्गीय किसानों पर इसका असर पड़ेगा। मंगलवार को व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिका समझौते पर जो तथ्य (फैक्ट शीट) जारी किये हैं, उसे बाद में थोड़ा बदला गया, लेकिन इससे समझौता का मु य केन्द्र नहीं बदला, जो पूरी तरह से अमेरिका के पक्ष में है और जिसके तहत भारत ट्रंप को जब चाहे समझौते के व्यापक विवरण में छेड़छाड़ करने का हक देता है। अगर यह रणनीतिगत स्वायत्तता का आत्मसमर्पण नहीं है, तो और क्या है? जैसा कि इस लेखक ने पहले एक अन्य आलेख में बताया था, ट्रंप-मोदी समझौता भू राजनीति पर, खासकर चीन से सुरक्षा खतरे से जुड़े मामलों में साझेदारी का हिस्सा है। ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री को अमेरिका की एशिया-प्रशांत सामरिक रणनीति चुनने के लिए मजबूर किया गया है। इस तरह, संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गलत नहीं हैं जब वे प्रधान मंत्री पर भारत के 1.4 अरब लोगों के हितों का समर्पण करने का इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री के पास वैश्विक दक्षिण के असली नेता के तौर पर उभरने का एक बड़ा मौका था। बदकिस्मती से भारत राष्ट्र, के नेता के रूप में वह चूक गए हैं और अब फिर से राष्ट्रीय हितों की कीमत पर ट्रंप को लुभाने के पुराने रास्ते पर चल रहे हैं?

# विविध समाचार

## पंजाब सरकार राज्य को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए वचनबद्ध : बलबीर सिंह

चंडीगढ़ ०३/०३ (संवाददाता): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा– निर्देशों अनुसार पंजाब को तम्बाकू मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरु किए अभियान के चलते पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्री डा. बलबीर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में हुक्का बार पर पाबंदी लगाने सहित तम्बाकू कंट्रोल में मिसाली काम किए गए है। डा. बलबीर सिंह इम्पलीमैंटेशन आफ डब्लयूएचओ– ऐमपावर एंड फ्रेमवर्क कनवैनशन आन तम्बाकू कंट्रोल (डब्लयूएचओ एफसीटीसी) आर्टीकल 5. 3 विषय पर करवाई तीन दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशाप के उद्घाटन उपरांत सभा को संबोधन कर रहे थे। यह वर्कशाप डिपार्टमैंट आफ कम्युनिटी मैडिसन एंड स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के रिसोर्स सैंटर फार तम्बाकू कंट्रोल (आरसीटीसी) और वाईटल स्ट्रैटिजीज के सहयोग के साथ करवाई गई थी। होटल माऊंटव्यू में करवाई इस वर्कशाप में 12 अलग–अलग राज्य से 35 डेलिगेट्स ने भाग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने डब्लयूएचओ फसीटीसी आर्टीकल 5.3 को लागू करने के लिए इमपारवरड समिति का गठन किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत ई–सिगरेट को अप्रवानित नशा घोषित करने वाला पहला राज्य भी है। उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 865 गाँवों ने पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पास होने उपरांत स्वंय को तम्बाकू मुफ्ध्त गाँव घोषित किया गया है। सेहत मंत्री ने आरसीटीसी टीम को 2018 से तम्बाकू कंट्रोल में अग्रणी भूमिका निभाने और इस महत्वपूर्ण वर्कशाप के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने आरसीटीसी के विषय–आधारित न्यूजलेटर 'तम्बाकू– फ्री टाईमज' का 29वें ऐडीशन जिसमें देश की तम्बाकू कंट्रोल गतिविधियों में डिजिटल दखध्ल के बढिया अभ्यासों को संकलित किया गया है, भी जारी किया। डिपार्टमैंट आफ कम्युनिटी मैडिसन और स्कूल आफ पब्लिक हैल्थ और आरसीटीसी के डायरैक्टर प्रो. सोनू गोयल ने डब्लयूएचओ फसीटीसी आर्टीकल 5.3 की स्थिति, तम्बाकू के प्रयोग को रोकने के लिए अलग–अलग राज्यों द्वारा किए जा रहे यत्नों और इनसे शिक्षा लेने की महत्ता के बारे में विस्तार के साथ बताया। उन्होंने पूरी सरकारी पहुँच के द्वारा तम्बाकू कंट्रोल को मजबूत करने, नैटवर्किंग और हिस्सेदारी को बढ़ाने और आरसीटीसी के द्वारा उपलब्ध स्रोतों जिसमें आनलाइन कोर्स और प्रकाशन शामिल है, के विस्तृत विवरण पर जोर दिया। उन्होंने तम्बाकू ऐंडगेम हब जिसका उदेश्य आर्टीकल 5.3 पर राज्य–विशेष नीतियों को विकसित करना और सूबा स्तरीय निगरान प्रणाली स्थापित करना है, के निर्माण के बारे में बताया। अतिरिक्त डिप्टी डायरैक्टर जनरल और डायरैक्टर ईएमआर, स्वास्थ्य और परिवार भलाई मंत्रालय, भारत सरकार डा.एल सवासतीचरन ने आर्टीकल 5.3 की महत्ता और इसको लागू करने में तेजी लाने के लिए इस प्रकार की वर्कशाप की जरूरत संबंधी चर्चा की।

## किसी गांव में पीने वाले पानी की समस्या ना आए : जिम्पा

चंडीगढ़ ०३/०३ (संवाददाता): पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा– निर्देशों अधीन पंजाब के जल स्पलाई और सैनीटेशन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने आज यहाँ पंजाब भवन में विभाग के कामों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि गर्मी के इस मौसम में किसी भी गाँव वासी को पानी की कोई किल्लत न आए और जिन इलाकों में पीने वाले पानी की स्पलाई उचित नहीं है वहाँ तुरंत परिवर्तनी प्रबंध किए जाएँ। उन्होंने पंजाब में कार्य अधीन 15 नहरी पानी योजनाओं को निश्चित समय में पूरा करके लोक अर्पित करने के आदेश भी जारी किए। इस मौके जल स्पलाई और सैनीटेशन मंत्री को बताया गया कि 2940 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के अलग– अलग इलाकों में 15 नहरी पानी आधारित योजनाएं कार्य अधीन है। इनमें से ज्यादातर योजनाएं इसी साल के अंत तक चालू हो जाएंगी और कुछ योजनाएं अगले साल तक चलने की संभावना है। इन योजनाओं के शुरू से 1706 गाँवों के 4 लाख 33 हजार 55 घरों के 24 लाख 73 हजार 261 लोगों को लाभ मिलेगा। जिम्पा ने हिदायत दिए कि नहरी पानी आध ाारित इन योजनाओं को समय पर पूरा करके लोक अर्पित किया जाए ताकि प्रत्येक गाँव वासी तक साफ पानी की स्पलाई सुनिश्चित हो। जिम्पा ने उच्च अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आवाम समर्थकीय कार्यध्योजनाएं लोक अर्पित करने मौके स्थानीय प्रतिनिधियों जैसे कि विधायक, एम.सी. , सरपंच– पंच आदि को जरूर शामिल किया जाए। इस मौके उन्होंने पहले से जारी योजनाओं, आर.ओ प्लांटों, ट्यूबवैलों और अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी हासिल की और जरूरी दिशां–निर्देश जारी किए। ब्रम शंकर जिम्पा ने होशियारपुर के बजवाड़ा सिवीरेज प्रोजैक्ट बारे भी जानकारी ली। उनको बताया गया कि इस प्रोजैक्ट के पूरा होने की समय सीमा अगस्त 2025 है। जिम्पा ने कहा कि यह प्रोजैक्ट हर हाल में निर्धारित समय में पूरा करके लोक अर्पित किया जाए। जल स्पलाई और सैनीटेशन मंत्री ने देहाती इलाकों में कूड़ा प्रबंधन के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की हिदायत भी की। मीटिंग में प्रमुख सचिव नीलकंठ अवहद, विभाग प्रमुख अमित तलवाड़, सभी चीफ इंजीनियर और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

## हिमाचल सरकार ने पूरा किया महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा– मुकेश अग्निहोत्री

ऊना ०३/०३ (संवाददाता): उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 1500–1500 रुपये देने का अपना वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही थी। बीजेपी वाले महिलाओं को कहते थे कि 1500 रुपये के लिए फॉर्म भरने में अपना समय बर्बाद ना करें। लेकिन जिला के जिन लोगों ने राज्य सरकार पर विश्वास जताया उनको आज जून की तिमाही के 4500–4500 रुपये एकमुश्त खाते में डाले गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने हरोली के कांगड़ में बुधवार को हुए सम्मान निधि ा वितरण के शुभारंभ समारोह में विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने के अपने वायदे को पूरा किया है। उन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में सम्मान निधि पाने वाली लाभार्थी महिलाओं को बधाई दी, वहीं महिला कल्याण के इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि योजना के पहले चरण में ऊना जिले की करीब सवा 7 हजार महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, उन्हें 3 करोड़ 27 जाख 60 हजार रुपये वितरित किए गए हैं। बता दें, कांगड़ में हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल तथा चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन बबलू भी उपस्थित रहे।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार पार्टी की पहचान देख कर पैसे नहीं डालती। महिला किसी भी पार्टी की हो प्रत्येक पात्र महिला 1500 रुपये की हकदार है और उनके खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जब 1 अप्रैल से प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये डालने का कार्य आरंभ किया था, तब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इसमें अड़ंगा लगवा दिया और उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने 15 सौ रुपये को महिलाओं के खाते में डालने पर रोक लगा दी थी। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खु ने फैसला किया कि महिलाओं को किए गए वायदे के अनुरूप अप्रैल, मई और जून माह की किश्तें एक साथ दी जाएंगी। यह मुख्यमंत्री की जनहितैषी सोच को दिखाता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी ने सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश की लेकिन उनके सभी पैंतरे विफल रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की लोकप्रियता का पैमाना उसका वायदा होता है और राजनेता की जुबान सबसे बड़ा भरोसा होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्रियों द्वारा किए गए वायदे पूर्ण होने पर जनता का विश्वास सरकार पर बनता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो दो बड़े वायदे किए थे, उन्हें पूरा कर लिया गया है। पहला वायदा पूरा करते हुए प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके उनके बुढ़ापे को सुरक्षित बनाया है। और अब महिलाओं को 1500 रुपये देने के बवायदे को पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की डोर एक ऐसी ईमानदार सरकार के हाथ में है जो अपने राज्य की जनता के हित में किए गए वायदों को पूर्ण करती है। उप मुख्यमंत्री ने हरोली की जनता का आभार जताते हुए कहा कि हरोली क्षेत्र की जनता ने उन्हें लगातार 25 वर्षों से सेवा करने का मौका दिया है। हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हरोली की जनता ने 1500 रुपये की बात पर विश्वास जताया और सबसे आगे बढ़कर फार्म भरे । इसी का नतीजा है कि जिले की करीब सवा 7 हजार लाथार्थियों में से करीब साढ़े 5 हजार लाभार्थी महिलाएं अकेले हरोली विस क्षेत्र की ही हैं। उन्हें समारोह में 4500–4500 रुपये प्रदान करते हुए करीब 2. 50 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

## राजा वडिंग को पुलिस विभाग में तबादलों से परेशानी क्यों : कंग

चंडीगढ़ ०३/०३ (संवाददाता): 'आप' ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग्ं द्वारा पंजाब पुलिस विभाग में तबादलों को लेकर जताई गई आपत्तियों पर सवाल उठाया है। आप ने कहा कि यह एक आम सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन राजा वडिंग्ं की परेशानी से संकेत मिलता है कि इन तबादलों के कारण शायद उनके निजी हित को क्षति पहुंच रही है। बुधवार को चंडीगढ़ पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद एवं आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि मान सरकार को आम लोगों से फीडबैक मिला था कि कुछ पुलिस कर्मी नशे के धंधे में शामिल हैं, इसलिए इस धंधे पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भारी संख्या में तबादला करने का फैसला किया है। कंग ने कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन तबादलों से वह परेशान क्यों हैं? कंग ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ राजा वडिंग्ं की कुछ निजी सेटिंग है। कंग ने राजा वडिंग्ं के इस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा कि मान सरकार कांग्रेस को वोट देने वाले पुलिस कर्मियों का तबादला कर रही है। कंग ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के नेता आम तौर पर पंजाब और यहां के लोगों के मुद्दों पर चुप रहते हैं। राजा वडिंग्ं और सुनील जाखड़ लॉरेंस बिश्नोई के गुजरात जेल से सामने आए वीडियो का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन वे पुलिस विभाग की कुछ नियमित कार्यप्रणाली पर आपत्ति जता रहे हैं। कंग ने कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस और भाजपा के नेता हमेशा से भ्रष्ट और माफिया लोगों को सरकारी संरक्षण देते रहे हैं।

## पंजाब में सात अन्य सी.बी.जी. प्रोजैक्ट साल के अंत तक होंगे कार्यशील : अमन अरोड़ा

चंडीगढ़ ०३/०३ (संवाददाता): पंजाब को देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस साल के अंत तक 7 अन्य कम्प्रैस्ड बायोगैस (सी.बी.जी.) प्रोजैक्ट कार्यशील होने की आशा है। यह प्रोजैक्ट सालाना 4.20 लाख टन पराली का उपभोग करके प्रति दिन 79 टन सी.बी. जी. पैदा करेंगे। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (पेडा) द्वारा राज्य में लागू किए जा रहे प्रोजैक्टों की समीक्षा के लिए बुलाई गई मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार ने 469.50 टन सीबीजी रोजाना की कुल सामर्थ्य वाले 38 प्रोजैक्ट अलॉट किए हैं, जिनमें फसल अवशेष– ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए किए जा रहे यत्नों में यह प्रोजैक्ट सहायक होंगे। इसके अलावा यह प्रोजैक्ट किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत पैदा करने के साथ–साथ कौशल और गैर–कौशल कामगारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में सी.बी.जी. प्रोजैक्टों के लिए भरपूर संभावनाएं हैं क्योंकि राज्य में हर साल लगभग 20 मिलियन टन ध ाान की पराली पैदा होती है, जिसमें से लगभग 10 मिलियन टन का ही वैज्ञानिक ढंग के साथ निपटारा किया जाता है।

## पौधरोपण कर मनाया गया पंजाब एंड सिंध बैंक का 117 वां स्थापना दिवस

जालंधर ०३/०३ (संवाददाता): पंजाब एंड सिंध बैंक, शाखा न्यू ग्रेन मार्किट के समूह स्टाफ सदस्यों ने अपने समाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए शाखा के बाहर पौध ाारोपण कर धरा को हरा भरा करने का संकल्प लिया। पौधारोपण कार्यक्रम में पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर मिलिंद बुचके मुख्यातिथि के तौर पर उपस्थित हुए। जोनल मैनेजर मिलिंद बुचके ने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पेड़ लगाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खाना खाना। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है, यह हमें जीवनदायिनी "ऑक्सीजन" प्रदान करते हैं। श्री मिलिंद बुचके ने सभी को वृक्षारोपण कर प्रकृति की अनमोल ध ारोहर को बचाने का भी आह्वान किया।बैंक के चीफ मैनेजर ओलिम्पन गुरदीप कुमार ने कहा कि पौधारोपण प्रति लोगों को किया जागरूक करते हुए कहा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने आगे कहा कि वायुमंडल तेजी से दूषित हो रहा है, ऐसे में यदि अब हम नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा।बैंक के शाखा मैनेजर स. तेजा सिंह के अनुसार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़–पौधों की अधिकता जरूरी है। इसलिए हमें अध्कि ाक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा और स्वच्छता में सहयोग देना चाहिए।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

# ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार　　राउरकेला, बुधवार 04 मार्च 2026

## मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच फंसे ओडिशा के लोग, नवीन पटनायक ने केंद्र से लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार

भुवनेश्वर ०२/०३ (संवाददाता): मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच, बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को भारत सरकार से क्षेत्र में फंसे ओडिशा के लोगों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। एक बयान में, पटनायक ने कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के कारण प्रवासी श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों और पर्यटकों सहित ओडिशा के कई लोग फंसे हुए हैं। हवाई संपर्क बाधित होने से कई लोग गंभीर अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा और कल्याण खतरे में है, और वे तत्काल सहायता के लिए देश की ओर देख रहे हैं।

पटनायक ने आगे कहा कि भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संघर्ष में फंसे सभी ओडिशावासियों की सुरक्षित निकासी और वापसी सुनिश्चित



करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। त्वरित कार्रवाई न केवल जीवन की रक्षा करेगी बल्कि घर पर अनगिनत परिवारों को भी आश्वस्त करेगी जो अपने प्रियजनों के कुशल-मंगल के बारे में जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह, एआईएडीएमके सांसद आई एस इनबादुराई ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हो रही स्थिति पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया।

विदेश मंत्री को लिखे पत्र में, इनबादुराई ने तमिलनाडु के परिवारों की चिंताओं को उजागर किया, विशेष रूप से एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, जिन्होंने केंद्र से मध्य पूर्वी देशों में रहने वाले भारतीयों, विशेषकर तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। इनबादुराई ने लिखा कि मैं संयुक्त अरब अमीरात सहित मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में व्याप्त तनावपूर्ण और बदलती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आपको यह पत्र लिख रहा हूं। इस संदर्भ में, हमारी पार्टी के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों और विशेष रूप से तमिलों की सुरक्षा के लिए किया गया अनुरोध तमिलनाडु के लाखों परिवारों की वास्तविक चिंता को दर्शाता है।

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि केंद्र सरकार इजरायल-ईरान संघर्ष के बीच फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ऐसी स्थितियों में बचाव कार्य के लिए तत्परता से काम करती है। पिछली सरकारों ने ऐसी व्यापक सहायता प्रदान नहीं की थी, जिसका प्रबंधन अब विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में अपने दूतावासों के माध्यम से कर रहा है।

## सरकार ने असली ओडिया नामों को बहाल करने के लिए अभियान शुरू किया

भुवनेश्वर ०२/०३ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने राज्य भर में जगहों के असली ओडिया नामों को वापस लाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। इसके लिए इंग्लिश स्पेलिंग में कॉलोनियल समय की गलतियों को ठीक किया गया है। रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डॉ. अरबिंद कुमार पाधी ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को सात दिनों के अंदर डिटेल्ड प्रपोज़ल जमा करने का निर्देश दिया। डॉ. पाधी ने ज़िलों, हेडक्वार्टर, सब-डिवीजन, ब्लॉक और तहसीलों के असली ओडिया नामों को वापस लाने पर ज़ोर दिया, जहाँ मौजूदा इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन ओडिया उच्चारण और कल्चरल पहचान को गलत तरीके से दिखाते हैं। इस कदम का मकसद ब्रिटिश शासन के दौरान आई गलतियों को खत्म करते हुए ओडिशा की भाषाई और



कल्चरल विरासत को बचाना है। सरकार ने केंद्रपाड़ा ज़िले में उदाहरणों पर ज़ोर दिया, जो कॉलोनियल उच्चारण की मुश्किलों से शुरू हुआ था। अधिकारियों ने असली ओडिया इस्तेमाल को दिखाने के लिए जैसे सुधारों का प्रस्ताव दिया। इसी तरह, खुर्दा से खोराधा, बालासोर से बालेश्वर और ज्योंझर से केंदुझार जैसे प्रपोज़ल शामिल हैं। 13 ज़िलों से रिपोर्ट पहले ही डिपार्टमेंट के पास पहुँच चुकी हैं, और नए सुझावों को विधायकों, स्कॉलर्स और नागरिकों की राय के साथ मिलाया जाएगा। सरकार जल्द ही सुझावों को फ़ाइनल करने की योजना बना रही है, ताकि यह पक्का हो सके कि ऑफ़िशियल रिकॉर्ड ओडिया फ़ोनेटिक्स और विरासत के हिसाब से हों। इस निर्देश में अर्जेंसी पर ज़ोर दिया गया है, और कलेक्टरों से रिव्यू में तेज़ी लाने और प्रपोज़ल जल्दी जमा करने का आग्रह किया गया है। ट्रांसलिटरेशन की गलतियों को ठीक करके, ओडिशा का मकसद कल्चरल पहचान को मज़बूत करना और अपनी ऐतिहासिक विरासत को मज़बूत करना है।

## थाईलैंड से बचाए गए सभी छह ओडिया मज़दूर अपने परिवारों से मिले

भुवनेश्वर ०३/०३ (संवाददाता): थाईलैंड में फंसे बाकी दो ओडिया युवक आज सुरक्षित ओडिशा पहुंच गए, जिससे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के दखल के बाद सभी छह युवकों की वापसी पूरी हो गई। केंद्रपाड़ा जिले के राजकनिका ब्लॉक के उपुलई गांव के प्रशांत कुमार राउत और कुजीपुर गांव के यशोबंत साहू कई सरकारी एजेंसियों की मिली-जुली कोशिशों के बाद राज्य पहुंचे।



चार और युवक 21 फरवरी को ही लौट आए थे। केंद्रपाड़ा जिले के राजकनिका ब्लॉक के छह युवक ङ्क बिजय कुमार स्वैन, हेमंत कुमार बेहरा, जयंत कुमार मल्लिक, यशोबंत साहू, और प्रशांत कुमार राउत, साथ ही भद्रक जिले के चांदबली ब्लॉक के मनोरंजन साहू ङ्क अगस्त 2025 में एक प्लाइवुड कंपनी में काम करने के लिए थाईलैंड गए थे। हालांकि, थाईलैंड पहुंचने के बाद, उन्हें कथित तौर पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युवकों ने दावा किया कि कंपनी के मालिक ने उनकी सैलरी नहीं दी और उन्हें काम करने के मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। फंसे और परेशान होकर, उन्होंने ओडिशा सरकार से अपनी वापसी में मदद मांगी। उनकी बुरी हालत की जानकारी मिलने पर, राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई शुरू की।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय; नई दिल्ली में ओडिशा सरकार के प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस; ओडिया भाषा, साहित्य और संस्कृति विभाग के तहत ओडिशा परिबार डायरेक्टरेट; लेबर और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट; और केंद्रपाड़ा और भद्रक के जिला प्रशासन की मिली-जुली कोशिशों से उन्हें बचाया और वापस लाया जा सका। आखिरी दो युवाओं की सुरक्षित वापसी के साथ, सभी छह अब अपने परिवारों के पास वापस आ गए हैं। ओडिशा पहुंचने के बाद, युवाओं ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभागों का समय पर दखल देने और उन्हें सुरक्षित घर लाने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया।

## आरएसपी ने कोक ओवन बैटरी नंबर 7 के कोक ड्राई कूलिंग प्लांट के लिए अनुबंध पर किए हस्ताक्षर

राउरकेला ०३/०३ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने कोक ओवन बैटरी नंबर 7 (सीओबी-7) के बीपीटीजी, बॉयलर और डीएम वाटर प्लांट (पीकेजी-3) सहित कोक ड्राई कूलिंग प्लांट के लिए टर्नकी आधार पर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड (कंसोर्टियम लीडर) और स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग एंटरप्राइजेज ऑफ कोक ओवन एंड बाय-प्रोडक्ट प्लांट्स एलएलसी (जेवी गिप्रोकोक्स एलएलसी) के कंसोर्टियम मेंबर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सीईटी, रांची परियोजना के लिए सलाहकार है।



इस अनुबंध पर 20 फ़रवरी 2026 को संघ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर आरएसपी के कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं), श्री सुदीप पाल चौधरी, आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं), श्री डी.के. साहू, आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं), श्री राहुल अग्रवाल, आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक (परियोजनाएं - वाणिज्यिक), श्री ए.के. साहू और आरएसपी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और सलाहकार सीईटी मौजूद थे । मेसर्स एल एंड टी टीम का नेतृत्व वीपी और हेड (एफबी), श्री ए.बी.दास ने किया था और मेसर्स जेवी (संयुक्त उद्यम) गिप्रोकोक्स एलएलसी का प्रतिनिधित्व उप निदेशक, श्री ए.कचुरा ने किया था। परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधक श्री सूर्य कुमार दाश, महाप्रबंधक (परियोजनाएं) हैं।

परियोजना में बैक प्रेशर टर्बाइन जेनरेटर (बीपीटीजी), बॉयलर और डीएम वाटर प्लांट के साथ एक अत्याधुनिक कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसमें सीओबी-7 से उत्पादित गर्म कोक को ठंडा करने के लिए प्रत्येक 55 टीपीएच के तीन कोक शीतलन कक्ष शामिल होंगे। ड्राई कूलिंग तकनीक बीपीटीजी के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए अपशिष्ट गर्मी की वसूली को सक्षम करेगी, जिससे ऊर्जा दक्षता में काफ़ी सुधार होगा, पर्यावरणीय उत्सर्जन को कम करेगा, और कोक ओवन संचालन की समग्र स्थिरता को बढ़ाएगा।परियोजना को अनुबंध की प्रभावी तिथि से 30 महीने की परियोजना अवधि के भीतर लागू किया जाना है। आरएसपी में आगामी सीओबी-7 के संचालन की शुरुआत के लिए कोक ड्राई कूलिंग प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण है।

यह रणनीतिक सहयोग कुशल ऊर्जा प्रबंधन में मदद करेगा और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रौद्योगिकियां इसकी उत्पादन क्षमताओं को मज़बूत करेंगी और दीर्घकालिक परिचालन उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगी।

## बच्चे के पिता से बदला लेने के लिए युवक ने तीन साल के बच्चे की हत्या कर दी

ज्योंझर ०३/०३ (संवाददाता): जिले के झुमपुरा ब्लॉक के नाहाबेड़ा पंचायत के मुंडा साही में तीन वर्षीय बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में पुलिस ने मंगलवार को एक युवक को गिरफ़्तार किया है।

आरोपी 25 वर्षीय श्रीतम मुंडा ने कथित तौर पर दो दिन पहले दुर्योधन मुंडा के बेटे लकी की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। बाद में उसने बच्चे के शव को सूखी नहर में फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि मुंडा साही के आदिवासी निवासियों ने करीब 10 दिन पहले माघे उत्सव मनाया था। उत्सव के दौरान कथित तौर पर आरोपी ने नशे की हालत में कुछ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद उत्सव समिति ने बैठक कर श्रीतम पर उसके कृत्य के लिए जुर्माना लगाया। आरोपी से जुर्माना वसूलने में दुर्योधन ने अहम भूमिका निभाई। तब से श्रीतम दुर्योधन से रंजिश रखता था और उससे बदला लेने के मौके की तलाश में था। रविवार दोपहर को आरोपी ने लकी का अपहरण कर लियाए जब बच्चा उसके घर के पास खेल रहा था। वह लड़के को पास के जंगल में ले गया और पत्थर से उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद उसने शव को खेंद्रा के पास सूखी कानपुर नहर में फेंक दिया और घर लौट आया। इस बीच चिंतित परिवार के सदस्यों ने लकी को विभिन्न स्थानों पर खोजाए लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

सोमवार को दुर्योधन ने इस संबंध में झुमपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लकी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को लड़के के अपहरण में श्रीतम की संलिप्तता के बारे में जानकारी मिली।

इसके बाद आरोपी को थाने लाया गया। चंपुआ के उप.विभागीय पुलिस अधिकारी ;एसडीपीओ बिजय कुमार मल्लिक ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया।

मंगलवार को उसे अपराध स्थल के पुनर्निर्माण के लिए जंगल और कानपुर नहर ले जाया गया। झुमपुरा के तहसीलदार रोहित बाग और आईआईसी सोमाबारी हांसदा की मौजूदगी में बच्चे का शव बरामद किया गया। एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है।

## आरएसपी के इस्पात जनरल हॉस्पिटल में क्रिटिकल स्पाइन सर्जरी से मरीज़ फिर से चलने में सक्षम हो पाया

राउरकेला ०३/०३ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के इस्पात जनरल हॉस्पिटल (आईजीएच) की विशेषज्ञ चिकित्सा टीम द्वारा की गई एक समय पर और महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी की सर्जरी ने 51 वर्षीय आरएसपी कर्मचारी को गतिशीलता और जीवन का एक नया अध्याय हासिल करने में मदद की। हॉट स्ट्रिप मिल-ढ्ढ के श्री सी.एस. प्रसाद जो दिसंबर 2025 से रीढ़ की हड्डी के तपेदिक का इलाज कर रहे थे, ने एक गंभीर जटिलता विकसित की लेकिन आईजीएच में त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप और उन्नत सर्जिकल प्रबंधन के बाद सफलतापूर्वक ठीक हो गए।



श्री प्रसाद को 17 जनवरी 2026 को आईजीएच में भर्ती कराया गया था, जब वह अचानक खड़े होने में असमर्थ हो गए और दोनों निचले अंगों में गंभीर कमजोरी विकसित हो गई, रीढ़ की हड्डी की तपेदिक की एक गंभीर और ख़तरनाक जटिलता है । स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए उसी दिन सहायक प्रबंधक, रेडियोलॉजी, श्री तापस कर की सहायता से एक एमआरआई की व्यवस्था की गई। स्कैन से प्रभावित स्तर पर मवाद संचय में वृद्धि का पता चला, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की ज़रूरत पड़ी।स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन और स्पाइनल कैनाल के डिकंप्रेशन के साथ आपातकालीन सर्जरी की तुरंत योजना बनाई गई और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं), डॉ. जे के आचार्य ने इसे आसान बनाया। इस जटिल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन, डॉ मनोज कुमार देव द्वारा किया गया था। । एनेस्थीसिया सहायता अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थीसिया), डॉ. संजुक्ता पानीग्रही और सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एनेस्थीसिया), डॉ. सी.के. कासी द्वारा प्रदान की गई थी । ऑपरेशन के दौरान सहायता गोधुली सिस्टर, सुनंदा सिस्टर और अर्चना सिस्टर द्वारा प्रदान की गई थी।

सर्जरी के बाद, श्री प्रसाद की हालत में लगातार सुधार हुआ और श्री प्रेमानंद स्वैन, फिजियोथेरेपिस्ट और उनकी टीम से मिली स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी सपोर्ट से, वे तीन हफ़्ते के अंदर वॉकिंग स्टिक की मदद से चलने लगे। स्वप्ना सिस्टर, सविता सिस्टर, एकता सिस्टर, अर्चना सिस्टर और दूसरे नर्सिंग स्टाफ ने ऑपरेशन के बाद उनकी अच्छी देखभाल की। उनकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि वे अगले दो से तीन हफ़्तों में अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएँगे। सफल रीढ़ की हड्डी की देखभाल अस्पताल की नैदानिक उत्कृष्टता और समन्वित बहु-विषयक दृष्टिकोण का एक और उदाहरण है।